12-03-2024

महतारी वंदन योजना

सुर्ख़ियों में क्यों?

- 10 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना शुरू की और योजना के तहत पहली किश्त का वितरण किया।

संबंधित प्रमुख बिंदु

- यह योजना राज्य की पात्र विवाहित महिलाओं को मासिक मासिक प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के रूप में 1000 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है।
- महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण सुनिश्चित करने, उन्हें वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने, स्त्री-पुरुष समानता को बढ़ावा देने और परिवार में महिलाओं की निर्णायक भूमिका को सुदृढ़ करने के लिए इसकी परिकल्पना की गई है।
- यह योजना राज्य की सभी पात्र विवाहित महिलाओं को लाभ प्रदान करेगी जिनकी आयु 1 जनवरी 2024 तक 21 वर्ष से अधिक है। विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्त महिलाएं भी इस योजना के लिए पात्र होंगी। योजना से लगभग 70 लाख महिलाएं लाभान्वित होंगी।
- सरकार ने महतारी वंदना योजना की पहली किश्त के तहत कुल 655 करोड़ रुपये का वितरण किया।

भारत - ईएफटीए व्यापार एवं आर्थिक साझीदारी समझौता

सुर्ख़ियों में क्यों?

- 10 मार्च 2024 को भारत - यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन (ईएफटीए) ने एक व्यापार एवं आर्थिक साझीदारी समझौता (टीईपीए) पर हस्ताक्षर किए।

समझौते की मुख्य विशेषताएं:

- ईएफटीए ने अगले 15 वर्षों में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के स्टॉक को 100 बिलियन डॉलर तक बढ़ाने और ऐसे निवेशों के माध्यम से भारत में 1 मिलियन प्रत्यक्ष रोजगार के सृजन की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्धता जताई है।
- एफटीए के इतिहास में पहली बार लक्ष्य-उन्मुख निवेश को बढ़ावा देने और रोजगारों के सृजन के बारे में कानूनी प्रतिबद्धता जताई जा रही है।
- ईएफटीए अपनी 92.2 प्रतिशत टैरिफ लाइनों की पेशकश कर रहा है जो भारत के 99.6 प्रतिशत निर्यात को कवर करता है। ईएफटीए के बाजार पहुंच प्रस्ताव में 100 प्रतिशत गैर-कृषि उत्पाद और प्रसंस्कृत कृषि उत्पाद (पीएपी) पर टैरिफ रियायत शामिल है।
- टीईपीए हमारी प्रमुख ताकत/रुचि के क्षेत्रों जैसे आईटी सेवाओं, व्यावसायिक सेवाओं, व्यक्तिगत, सांस्कृतिक, खेल और मनोरंजक सेवाओं, अन्य शिक्षा सेवाओं, ऑडियो- विजुअल सेवाओं आदि में हमारी सेवाओं के निर्यात को प्रोत्साहित करेगा।
- ईएफटीए की सेवाओं की पेशकश में सेवाओं की डिजिटल डिलीवरी, वाणिज्यिक उपस्थिति और प्रमुख कर्मियों के प्रवेश और अस्थायी प्रवास के लिए बेहतर प्रतिबद्धताओं और निश्चितता के माध्यम से बेहतर पहुंच शामिल है।
- टीईपीए में नर्सिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट आदि जैसी व्यावसायिक सेवाओं में पारस्परिक मान्यता समझौतों के प्रावधान हैं।
- टीईपीए में बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित प्रतिबद्धताएं ट्रिप्स स्तर पर हैं। स्विट्जरलैंड के साथ आईपीआर अध्याय, जहां आईपीआर के लिए उच्च मानक हैं, हमारी मजबूत आईपीआर व्यवस्था को

दर्शाता है। जेनेरिक दवाओं में भारत के हितों और पेटेंट की सदाबहारता (एवरग्रीनिंग) यानी सदाबहार की प्रक्रिया में शामिल पेटेंट कानून और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून के विशिष्ट पहलू, से संबंधित चिंताओं को पूरी तरह से संबोधित किया गया है।

- भारत सतत विकास, समावेशी विकास, सामाजिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का संकेत देता है | व्यापार प्रक्रियाओं की पारदर्शिता, दक्षता, सरलीकरण, सामंजस्य और स्थिरता को बढ़ावा देता है

- टीईपीए हमारे निर्यातकों को विशेष इनपुट तक पहुंच को सशक्त बनाएगा और अनुकूल व्यापार और निवेश माहौल तैयार करेगा। इससे भारत में निर्मित वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और साथ ही सेवा क्षेत्र को अधिक बाजारों तक पहुंचने के अवसर मिलेंगे।
- टीईपीए यूरोपीय संघ के बाजारों में एकीकृत होने का अवसर प्रदान करता है। स्विट्ज़रलैंड का 40 प्रतिशत से अधिक वैश्विक सेवा निर्यात यूरोपीय संघ को होता है। भारतीय कंपनियां यूरोपीय संघ तक अपनी बाजार पहुंच बढ़ाने के लिए स्विट्जरलैंड को आधार के रूप में देख सकती हैं।
- टीईपीए बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी, विनिर्माण, मशीनरी, फार्मास्यूटिकल्स, रसायन, खाद्य प्रसंस्करण, परिवहन और लॉजिस्टिक्स, बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं और बीमा जैसे क्षेत्रों में घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करके "मेक इन इंडिया" और आत्मनिर्भर भारत को गति देगा।
- टीईपीए भारत में अगले 15 वर्षों में व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण के लिए बेहतर सुविधाओं सहित भारत के युवा महत्वाकांक्षी कार्यबल के लिए बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष रोजगारों के सृजन में तेजी लाएगा। टीईपीए सटीक इंजीनियरिंग, स्वास्थ्य विज्ञान, नवीकरणीय ऊर्जा, नवोन्मेषण और अनुसंधान एवं विकास में प्रौद्योगिकी सहयोग और विश्व की अग्रणी प्रौद्योगिकियों तक पहुंच की सुविधा भी प्रदान करता है।

EFTA क्या है?

- EFTA एक अंतर-सरकारी संगठन है जिसे वर्ष 1960 में उन यूरोपीय राज्यों के लिये एक वैकल्पिक व्यापार ब्लॉक के रूप में स्थापित किया गया था जो यूरोपीय संघ (EU) में शामिल होने में असमर्थ या अनिच्छुक थे।
- EFTA में आइसलैंड, लिकटेंस्टीन, नॉर्वे और स्विट्ज़रलैंड शामिल हैं, जो यूरोपीय संघ के अंग नहीं हैं, लेकिन विभिन्न समझौतों के माध्यम से इसके एकल बाज़ार तक पहुँच रखते हैं।
- ईएफटीए भारत का 9 वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, जिसका 2020-21 में भारत के कुल व्यापारिक व्यापार का लगभग 2.5% हिस्सा है।
- ईएफटीए को भारत के निर्यात की मुख्य वस्तुएं कपड़ा, रसायन, रत्न और आभूषण, मशीनरी और फार्मास्यूटिकल्स हैं।
- ईएफटीए से भारत के आयात की मुख्य वस्तुएं मशीनरी, रसायन, कीमती धातुएं और चिकित्सा उपकरण हैं।

अभ्यास कटलैस एक्सप्रेस 2024

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में भारत के पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन (1टीएस) के प्रमुख जहाज आईएनएस तीर ने अभ्यास कटलैस एक्सप्रेस - 2024 में भाग लिया।

संबंधित प्रमुख बिंदु

- यह अभ्यास 26 फरवरी से 08 मार्च 2024 तक सेशेल्स के पोर्टविक्टोरिया में आयोजित किया गया है | इस अभ्यास का उद्घाटन सेशेल्स के राष्ट्रपति ने भारत, अमेरिका और अफ्रीकी देशों के गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में किया।

- इस अभ्यास का समापन 08 मार्च 2024 को सेशेल्स रक्षा अकादमी, इलेपर्सिवरेंस में आयोजित अंतिम समारोह में हुआ। भारतीय नौसेना साल 2019 से इस अभ्यास में भाग ले रही है।
- इससे पहले आईएनएस तीर ने 01 से 03 मार्च 2024

तक सेशेल्स तट रक्षक के साथ संयुक्त ईईजेड निगरानी अभियान में भाग लिया था।

- सेशेल्स में आईएनएस तीर की मौजूदा तैनाती और अभ्यास कटलैस एक्सप्रेस में भागीदारी संयुक्त प्रशिक्षण एवं सहभागिता को बढ़ावा देने तथा मित्रता के सेतु के निर्माण की दिशा में भारतीय नौसेना व क्षेत्रीय नौसेनाओं के बीच घनिष्ठ संबंधों को उजागर करती है।
- कटलैस एक्सप्रेस पूर्वी अफ्रीका और पश्चिमी हिंद महासागर में राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित एक वार्षिक समुद्री अभ्यास है।

'जल शक्ति अभियान : कैच द रेन-2024'

सुर्ख़ियों में क्यों?

- केंद्रीय जल मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 09 मार्च, 2024 को नई दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में "जल शक्ति अभियान : कैच द रेन" अभियान के पांचवें संस्करण का शुभारंभ किया।

संबंधित प्रमुख बिंदु

- इस वर्ष का थीम "नारी शक्ति से जल शक्ति" है जिसके तहत अभियान में जल संरक्षण एवं प्रबंधन में महिलाओं की अभिन्न भूमिका पर बल दिया गया है।
- इस कार्यक्रम की शुरुआत 'जल कलश' समारोह के साथ हुआ, जो भविष्य में जल संरक्षण एवं इसके सतत उपयोग के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- यह अभियान पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सहयोग से राष्ट्रीय जल मिशन, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प विभाग के अंतर्गत आता है।
- इस वर्ष इस अभियान के तहत निम्नलिखित प्रमुख विषयों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा-
- जल संरक्षण एवं वर्षा जल संचयन
- सभी जल निकायों की गणना, भू-टैगिंग एवं सूची तैयार करना; जल संरक्षण के लिए वैज्ञानिक योजनाएं बनाना
- सभी जिलों में जल शक्ति केंद्रों की स्थापना
- सघन वनीकरण और
- जागरूकता सृजन
- जल निकायों से गाद निकालना और उनकी सफाई
- भूजल रिचार्ज के लिए त्यागे हुए/निष्क्रिय बोरवेलों का पुनरूद्धार
- राज्य के राजस्व रिकॉर्ड की सावधानीपूर्वक मैपिंग एवं नियमित अपडेट के साथ जल निकायों की जियो-टैगिंग
- जल निकायों के जलग्रहण क्षेत्रों में सघन वनीकरण करना
- जल संरक्षण के लिए लद्दाख में स्तूपों जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फ का संचयन और
- छोटी नदियों का कायाकल्प।
- गौरतलब है कि वर्ष 2020 में जल शक्ति मंत्रालय ने 'कैच द रेन' (सीटीआर) अभियान शुरू किया था।
- प्रधानमंत्री के जल संचय मंत्र से प्रेरित होकर, जल शक्ति मंत्रालय ने पूरे देश में जल संरक्षण के काम में तेजी लाने के लिए जन भागीदारी द्वारा जमीनी स्तर पर जल संरक्षण को बढ़ावा देने हेतु यह अभियान शुरू किया था।
- इसका उद्देश्य सभी स्थितियों के आधार पर जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल बारिश के पानी को संग्रहीत करने के लिये वर्षा जल संचयन संरचना (Rain Water Harvesting Structures- RWHS) का निर्माण करना है।

जल शक्ति अभियान के बारे में

- जल शक्ति अभियान को 1 जुलाई, 2019 को प्रारंभ किया गया था। यह अभियान सभी हितधारकों को जल संरक्षण अभियान के दायरे में लाने के लिये व्यापक जनांदोलन है।
- इस अभियान के तहत जल संकट से जूझ रहे देश के 256 ज़िलों को शामिल किया गया था।
- जल शक्ति अभियान का उद्देश्य मानसून की शुरुआत से पहले कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण,

मौजूदा तालाबों और जल निकायों को पुनर्जीवित करके नए जल निकायों का निर्माण, चेक डैम का प्रावधान, आर्द्रभूमि और नदियों का कायाकल्प करके वर्षा जल का दोहन करना है।

- इसके तहत देश में सभी जल निकायों को जियो टैगिंग करके और इस डेटा का उपयोग करके वैज्ञानिक एवं डेटा-आधारित जिला स्तरीय जल संरक्षण योजना बनाने के लिये एक डेटा-बेस बनाने की भी योजना है।
- जल शक्ति मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय जल मिशन, इसके कार्यान्वयन के लिये नोडल एजेंसी है।

सेला सुरंग (Sela Tunnel)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- 09 मार्च, 2024 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश में सेला सुरंग परियोजना को वर्चुअल तरीके से राष्ट्र को समर्पित किया।

संबंधित प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि इस सुरंग की आधारशिला 09 फरवरी, 2019 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने रखी थी और इसका निर्माण कार्य 01 अप्रैल, 2019 को शुरू हुआ था।
- सेला सुरंग दुनिया की सबसे लंबी द्वि-लेन सुरंग है, जिसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा 13,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर किया गया है, जिसकी लागत 825 करोड़ रुपये है।
- असम में तेजपुर को अरुणाचल प्रदेश में पश्चिम कामेंग जिले के तवांग से जोड़ने वाली यह सुरंग तवांग को हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करेगी, सशस्त्र बलों की तैयारियों को मजबूती देगी और सीमा क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ाएगी।

उन्नति (उत्तर पूर्व परिवर्तनकारी औद्योगीकरण) योजना

सुर्ख़ियों में क्यों?

- 09 मार्च, 2024 को अरूणाडल प्रदेश में 'विकसित भारत - विकसित उत्तर पूर्व' कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने उत्तर पूर्व के लिए नई औद्योगिक विकास योजना, उन्नति (Uttar-Purva Transformative Industrialization) की शुरुआत की।

संबंधित प्रमुख बिंदु

- यह योजना उत्तर पूर्व में औद्योगिक परितंत्र को मजबूत करेगी, नए निवेश को आकर्षित करेगी, नई विनिर्माण और सेवा इकाइयों को स्थापित करने में मदद करेगी और उत्तर पूर्व के राज्यों में रोजगार को बढ़ावा देगी।
- 10,000 करोड़ रुपये की इस योजना को पूरी तरह से भारत सरकार फंड मुहैया कराएगी और इसमें उत्तर पूर्व के सभी 8 राज्यों को शामिल किया गया है।
- यह योजना अनुमोदित इकाइयों को पूंजी निवेश, ब्याज छूट और विनिर्माण तथा सेवाओं से जुड़े प्रोत्साहन के लिए प्रोत्साहन प्रदान करेगी। पात्र इकाइयों के आसान एवं पारदर्शी पंजीकरण के लिए एक पोर्टल भी शुरू किया जा रहा है।
- उन्नति योजना औद्योगिक विकास को उत्प्रेरित करने और उत्तर पूर्व क्षेत्र के आर्थिक विकास में सहायता करेगी।